

(c) the entire expenditure on providing assistance is met by the Central Government.

Appointment of Chairman of Sugar Enquiry Commission

6334. SHRI M. M. HASIIM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) in view of the sudden death of Mr. Justice Sinha, Chairman of the Sugar Enquiry Commission, whether Government propose to appoint another Chairman so that the report of the Commission is submitted by August, 1971;

(b) if so, the name of the new Chairman; and

(c) the extension of time granted to the Commission to present its report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH): (a) and (b). Selection of the new Chairman of the Sugar Industry Enquiry Commission in place of late Mr. Justice Sinha is under consideration. The appointment is like by to be made shortly.

(c) Government have extended the time-limit for submission of Report by the Commission upto 29th February, 1972.

Visit of Indian Forest Service Central Committee to Orissa

6335. SHRI P. GANGADEB: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Indian Forest Service Central Committee has not visited the State of Orissa since 1970;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the same Committee visited other States in 1970 except Orissa;

(d) whether Government propose to ask the Committee to visit Orissa; and

(e) if so, when it is likely to visit Orissa?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH): (a) No Committee named "Indian Forest Service Committee" has been constituted by the Government of India for visiting the States.

(b) to (e). Does not arise.

केन्द्रीय श्रमिक संगठन को मान्यता देना

6336. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक केन्द्रीय संगठन को मान्यता देने के लिये क्या आधार अपनाया जाता है;

(ख) क्या किसी केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन ने सरकार से मांग की है कि उसे मान्यता दी जाये; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा अनुरोध कब किया गया था और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री धार० के० खाडिलकर) : (क) भारतीय श्रम सम्मेलन जैसे त्रिपक्षीय सलाहकार निकायों में प्रतिनिधित्व के लिए केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन के रूप में मान्यता के लिए 1959 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 17वें अधिवेशन द्वारा निर्धारित कसौटियां ये हैं कि:-

(i) संगठनों का अखिल भारतीय स्वरूप होना चाहिए;

(ii) संगठनों की अनेक राज्यों में व्याप्त न्यूनतम सदस्य संख्या एक लाख होनी चाहिए; और

(iii) संगठनों की कम से कम अधिकांश उद्योगों में पर्याप्त सदस्य-संख्या होनी चाहिए ।

(ख) जी हां । अनेक संगठनों ने इस प्रकार की मान्यता के लिए प्रार्थनाएं की हैं ।

(ग) प्रार्थनाएं समय-समय पर की गई हैं । कुछ संगठनों को केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों के रूप में मान्यता देने के प्रश्न पर फरवरी, 1966 में हुए स्थायी श्रम समिति के अधिवेशन में विचार किया गया । यह स्वीकार किया गया कि इस सम्बन्ध में यथा पूर्व स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए । तथापि, इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं ।